राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

वॉल्यूम 31, सं 2, अक्टूबर, 2022

इंफोमेटिक्स

संपादकीय संयोजन : प्रिस्का लाकड़ा

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर पोर्टल लॉन्च किया

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य - पावर @ 2047 का समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित, यह पोर्टल सोलर रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए आवेदन प्रक्रिया की निगरानी करने में सक्षम बनाता है, जो पंजीकरण से शुरू होता है और संयंत्र की स्थापना और निरीक्षण के बाद उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सब्सिडी की अंतिम रिलीज के साथ समाप्त होता है।

स्मरणोत्सव को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, "हम आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बनाने के लिए संकल्पित हैं। आज हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। अब तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से लगभग 170 गीगावॉट क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि घरों में सौर पैनलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इससे देश में बिजली की खपत और बिलों को कम करने में मदद मिलेगी। इससे हर साल निम्न-मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों के बिजली बिलों के रूप में 50 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी।"

माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ बिजली बचाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। हमारा वितरण घाटा दोहरे अंकों में है, जबकि दुनिया के विकसित देशों में यह एकल अंक में है। इसमें सोलर मदद कर सकता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभों पर भी प्रकाश डाला और कहा, "हम किसानों को सोलर पंप की

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर @ 2047 समापन समारोह में सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

सुविधा प्रदान कर रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं।" उन्होंने दोहराया, "बिजली बचाने का मतलब भविष्य को समृद्ध बनाना है।"

- सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब, श्री भगवंत मान ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा का शुभारंभ किया

माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब, श्री भगवंत मान ने राज्य में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली, सारथी का शुभारंभ किया। यह सेवा राज्य के नागरिकों को पारदर्शी तरीके से उनके कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप से एक क्लिक के साथ लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।

ऑनलाइन सुविधा सेवा केंद्रों पर उपलब्ध मौजूदा ऑफलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा के साथ मिलकर काम करेगी, लेकिन ऑफलाइन सेवा के मामले में, आवेदकों को पहले ऑनलाइन ट्रैफिक संकेत परीक्षण देना होगा।

माननीय सीएम ने कहा, "इससे चौबीसों घंटे अपने घरों में आराम से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी।" उन्होंने आगे कहा, "इस फैसले से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पिछले साल 5.21 लाख लोगों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाया था, लेकिन अब किसी आवेदकों को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।"

- सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब, श्री भगवंत मान, पंजाब में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा का शुभारंभ करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री, केरल, श्री पिनाराई विजयन, ने आधार आधारित थंडापर प्रणाली का शुभारंभ किया

माननीय मुख्यमंत्री, केरल, श्री पिनाराई विजयन ने वर्चुअल रूप से राज्य में आधार-आधारित थंडापर प्रणाली का उद्घाटन किया। थंडापर एक 13-अंकीय लंबा अद्वितीय पहचानकर्ता है जो राज्य भर में भूमि पार्सल के स्वामित्व को मैप करता है। यह भूमि मालिक के आधार पहचानकर्ता या आधार पहचानकर्ताओं के संयोजन (भूमि के संयुक्त या संस्थागत स्वामित्व के मामले में) को जोड़कर बनाया जा सकता है।

यह आयोजन श्री के. राजन, माननीय राजस्व मंत्री, श्री एंटनी राजू, माननीय परिवहन मंत्री, श्री वी. शिवनकुट्टी, माननीय सामान्य शिक्षा मंत्री, डॉ ए. जयतिलक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) और श्री पी. वी. मोहन कृष्णन, उपमहानिदेशक और राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी केरल की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। राज्य राजस्व विभाग और एनआईसी केरल के कई वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन में, श्री एंटनी राजू ने माननीय राजस्व मंत्री श्री के. राजन द्वारा राज्य भर में अपनी भूमि अधिकार के लिए थंडापर प्राप्त किया।

इस प्रणाली के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एनआईसी के ReLIS (राजस्व भूमि सूचना प्रणाली) सूट के आधार पर विकसित किया गया है।

यूनिक थंडापर से पहले, एक भूमि पार्सल में कई थंडापर संख्याएँ हो सकती थीं, यदि भूमि कई बार पंजीकृत की गई थी। इसने कई विसंगतियों को जन्म दिया, जैसे कि बेनामी भूमि का प्रचलन या प्रॉक्सी स्वामित्व वाली भूमि। इससे संपत्ति कर भुगतानों को ट्रैक करने में कठिनाई हुई जो इस प्रणाली द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है।

चूंकि स्वामित्व की जानकारी अधिक पारदर्शी हो जाती है, व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि को ट्रैक करना और उसकी पहचान करना आसान हो जाएगा। भूमि सुधार अधिनियमों के तहत अतिरिक्त भूमि को राज्य के भूमिहीन किसानों को पुनर्वितरित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना थंडापर नंबर थंडापर पोर्टल या डिजिलॉकर के माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर सकता है।

– सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री, केरल, श्री पिनाराई विजयन, एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से आधार-आधारित अद्वितीय थंडापर प्रणाली का उद्घाटन करते हुए

माननीय परिवहन मंत्री, श्री एंटनी राजू, माननीय राजस्व मंत्री श्री के. राजन से अपना थंडापर नंबर प्राप्त करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री, असम, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल का शुभारंभ किया

माननीय मुख्यमंत्री असम, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने 22 अगस्त 2022 को असम के राज्य सार्वजनिक खरीद (एसपीपी) पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक, असम सरकार, एनआईसी असम और एनआईसी चेन्नई के अधिकारियों ने (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) भाग लिया।

एसपीपी पोर्टल असम सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2017 के दायरे में आने वाले असम सरकार के विभागों, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य संस्थानों की सभी निविदा-संबंधी सूचनाओं तक पहुंचने के लिए एक एकीकृत मंच है। यह बोलीदाताओं और नागरिकों को किसी भी खरीद-संबंधी जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है और असम सरकार की सभी निविदाओं के लिए निस्संदेह एकल स्रोत के रूप में कार्य करती है। निविदा से संबंधित सभी जानकारी आम जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और खरीद संस्थाओं द्वारा वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद पर विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

एसपीपी पोर्टल निम्नलिखित सूचनाओं को एकत्रित करता है:

- स्वचालित वेब-सेवा एपीआई के माध्यम से https://assamtenders.gov.in (जीईपीएनआईसी एप्लिकेशन) पर प्रकाशित ऑनलाइन निविदाएं
- स्वचालित वेब-सेवा एपीआई के माध्यम से पीएमजीएसवाई (जीईपीएनआईसी एप्लिकेशन) पर प्रकाशित असम के लिए ऑनलाइन निविदाएं
- स्वचालित वेब-सेवा एपीआई के माध्यम से जीईएम पर प्रकाशित असम के लिए निविदाएं
- 25 लाख के न्यूनतम मूल्य से नीचे की मैनुअल निविदाएं, खरीद करने वाली संस्थाओं द्वारा एसपीपी पोर्टल पर प्रकाशित की जाएंगी।

खरीद करने वाली संस्थाओं (विभागीय उपयोगकर्ताओं) के पास वार्षिक खरीद योजना, मैनुअल निविदाएं और अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा है। पोर्टल विभागीय उपयोगकर्ताओं को निविदा डेटा प्रदर्शित करने के लिए एक डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करता है, प्राथमिक उद्देश्य एक नजर में जानकारी प्रदान करना है। यह जनता को विभिन्न प्रकार की निविदाओं की खोज करने और उन्हें निविदा गतिविधि, निविदा मूल्य और निविदा क्षेत्र जैसे मानदंडों के अनुसार क्रमबद्ध करने के लिए एक ''खोज'' सुविधा भी प्रदान करता है । निविदाओं को संगठन, श्रेणी, जीईपीएनआईसी और जी ई एम बोलियों के अनुसार भी फिल्टर किया जा सकता है।

पोर्टल पर एक शिकायत मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक फीडबैक मॉड्यूल के जरिए फीडबैक भी दे सकते हैं।

– कविता बरकाकोटी, असम

माननीय मुख्यमंत्री, असम, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा, असम के राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री, मेघालय, श्री कॉनराड संगमा ने एमएसपीएसडीसी पोर्टल का शुभारंभ किया

माननीय मुख्यमंत्री, मेघालय, श्री कॉनराड संगमा ने मुख्य आयुक्त श्री एम. एस. राव और राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी श्री टी. दखार की उपस्थिति में योजना भवन, शिलांग में मेघालय राज्य लोक सेवा वितरण आयोग (एमएसपीएसडीसी) के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया।

लॉन्च के दौरान बोलते हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह नागरिक केंद्रित शासन प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है और मूल रूप में सरकारी विभागों द्वारा नागरिकों को समयबद्ध सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से सरकार जो हासिल करने की कोशिश कर रही है । उन्होंने आगे कहा कि एकीकृत वेब पोर्टल नागरिक-केंद्रित शासन प्राप्त करने और समग्र वितरण तंत्र में सुधार की दिशा में एक कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी 188 सेवाओं को जल्द से जल्द पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा और सभी स्तरों पर विभागों से समय-सीमा का पालन करने का आग्रह किया ताकि कोई देरी न हो।

पोर्टल को नागरिकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला नागरिक भी राज्य में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पोर्टल की सेवाओं का लाभ उठा सकता है।

- सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री, मेघालय, श्री कॉनराड संगमा, योजना भवन, शिलांग में एकीकृत एमएसपीएसडीसी वेब पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री, असम, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा, ने कृतज्ञता सेवाओं के लिए पीएसके को समर्पित किया

माननीय मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने 30 जुलाई 2022 को कामरूप के जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान 27 कृतज्ञता पेंशन सेवा केंद्रों (पीएसके) को नागरिकों को समर्पित किया। उन्होंने कृतज्ञता पोर्टल की कार्यक्षमता की सराहना की, जो ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है और जिससे पेंशन प्रक्रिया के संचालन को सरल बनाया जा सके। अब तक, सिस्टम द्वारा 5000 से अधिक पीपीओ तैयार किए जा चुके हैं।

ये पीएसके सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे जो पेंशनभोगियों को कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत ऑनलाइन फॉर्म जमा करने, स्कैन की गई सेवा पुस्तकों को अपलोड करने, और जीवन प्रमाण सेवाओं के लिए पंजीकृत बायोमेट्रिक्स उपकरणों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

- कविता बरकाकोटी, असम

माननीय मुख्यमंत्री, असम, डॉ हिमंत बिस्वा, राज्य भर में 27 पेंशन सेवा केंद्रों का शुभारंभ करते हुए

मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर, डॉ अरुण कुमार मेहता ने ई–उन्नत पोर्टल लॉन्च किया

जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता ने देश के सबसे युवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए एकीकृत, समेकित, सुलभ और पारदर्शी (ई-उन्नत) सेवा पोर्टल लॉन्च किया। यह जम्मू और कश्मीर को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहला केंद्रशासित प्रदेश बनाता है, जो एक ही छत के नीचे कई नागरिक केंद्रित सेवाओं को सक्षम करने के लिए मेरी पहचान-राष्ट्रीय एकल साइन-ऑन का उपयोग करता है ।

नागरिक अब कई सरकारी सेवाओं के लिए पोर्टल https://eunnat.jk.gov.in पर पहुंच सकते हैं और खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। लाडली बेटी और विवाह सहायता योजना के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, निर्भरता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, वर्तमान में पोर्टल पर कुछ वित्तीय सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं ।

इस अवसर पर, डॉ मेहता ने विभिन्न विभागीय सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा प्रदान करके नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

सीएस जम्मू-कश्मीर ने यह भी कहा, ''सरकार का संकल्प सभी सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना, मानव हस्तक्षेप को कम करना और ''आप का मोबाइल, हमारा दफ्तर'' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सेवा वितरण के लिए सरकारी कार्यालयों में शारीरिक रूप से आने की मजबूरी को दूर करना है ।

सहभागितापूर्ण शासन में समर्थन के एक स्तंभ के रूप में जनता की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए, उन्होंने जनता से रैपिड असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से विभागीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिक्रिया साझा करने की अपील की क्योंकि इससे सरकार को जनता की अपेक्षाओं का आकलन करने और आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति मिलेगी।

- सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर, डॉ अरुण कुमार मेहता, ई-उन्नत पोर्टल लॉन्च करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम, श्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए ऑनलाइन परमिट प्रणाली की शुरुआत की

माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस 2022 समारोह के दौरान नामची, सिक्किम में राज्य के प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन परमिट प्रणाली का शुभारंभ किया ।

पड़ोसी देशों के साथ सिक्किम की निकटता के कारण, सभी विदेशी नागरिकों को राज्य के किसी भी हिस्से में जाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, विदेशियों और भारतीय नागरिकों दोनों को सिक्किम के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अलग परमिट की आवश्यकता होती है जिसे संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) के रूप में जाना जाता है। विशिष्ट मार्ग और दिनों की संख्या सहित विशिष्ट स्थलों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी किया जाता है। दोनों परमिट सिक्किम पुलिस की चेक पोस्ट शाखा द्वारा जारी किए जा रहे हैं।

अब से, एनआईसी द्वारा विकसित ऑनलाइन सिस्टम परमिट आवेदन प्रक्रिया को डिजिटाइज किया जायेगा और यात्रियों और ट्रैवल एजेंटों दोनों को डिजिटल मोड में पास के हेतु आवेदन करने में सक्षम करेगा। जारी किए गए परमिट में त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्यूआर) होते हैं जिन्हें मोबाइल फोन या क्यूआर बारकोड रीडर पर पढ़ा जा सकता है।

- सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम, श्री प्रेम सिंह तमांग, राज्य के प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए ऑनलाइन परमिट प्रणाली का शुभारंभ करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा, श्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रीय ई–विधान एप्लिकेशन (नेवा) का शुभारंभ किया

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 8 अगस्त 2022 को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का शुभारंभ किया।

नेवा एप्लिकेशन के लॉन्च के साथ, हरियाणा विधानसभा के माननीय सदस्य सत्र की कार्यवाही को पढ़ने और कागज पर नियमित रूप से कारोबार करने के बजाय डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने में सक्षम होंगे ।

कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने एनआईसी हरियाणा टीम द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य विधानसभा में आवेदन के सफल कार्यान्वयन के लिए श्री दीपक बंसल, डीडीजी और एसआईओ की भी सराहना की।

- सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा, श्री मनोहर लाल, हरियाणा राज्य विधानसभा के लिए नेवा एप्लिकेशन लॉन्च करते हुए

मध्य प्रदेश सरकार और एनआईसी ने ई–ग्रंथालय के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

मध्य प्रदेश में शिक्षा क्रांति लाने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एनआईसी के साथ 528 सरकारी कॉलेजों और 16 सरकारी कॉलेजों में एनआईसी द्वारा विकसित पुस्तकालय सूचना प्रबंधन प्रणाली, ई-ग्रंथालय को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभागों और एनआईसी मध्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच माननीय शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समारोह को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के 16 लाख छात्रों को लाभ होगा। इस सॉफ्टवेयर से छात्र दुर्लभ और महंगी किताबों का डिजिटल फॉर्मेट में लाभ उठा सकेंगे। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।

वर्तमान में देश में 28000 से अधिक शिक्षण संस्थान ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं। यह सेवा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। छात्र इस सुविधा का लाभ केवल एप पर अपना पंजीकरण कराकर उठा सकते हैं । एनआईसी के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि ऐप के उचित उपयोग के संबंध में राज्य भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में तैनात प्रोफेसरों और सहायक कर्मचारियों को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार और एनआईसी मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश में ई-ग्रंथालय के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे में नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिए News पर जायें https://informatics.nic.in/news